appeared in the voters' list of Assam of 1971 and 1977 would be eligible to be enrolled as voters now; and

(c) if the answer of (b) is in the affirmative, what steps have been taken by Government to guarantee that all such names are actually entered in the voters' lists?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) Assam has been witnessing a prolonged agitation since the second half of 1979, initially for the deletion of names of foreign nationals from electoral rolls, then for the postponement of elections which were due to be held in the first week of January, 1980, and again, for the detection and deportation of foreign nationals.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राजस्थान की लूनी, सूकड़ी और जीजडी नदियों को बाढ़ का प्रभाव

873. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में लूनी, सूकड़ी और जोजडी नदियों को बाढ से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं ;

(ख) इस वर्ष कौन से क्षेत्रों पर कितना प्रभाव पड़ा है तथा किस किस्म की हानि हुई है और जान व माल की कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई स्थाई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस योजना के लिए केन्द्र ने इस वर्ष कितना धन दिया है और अगले वर्ष कितना धन दिया जायेगा ; और

(ङ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख). इस वर्ष जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जालोर और बाड़मेर जिलों के क्षेत्र प्रभावित हुए थे । जो हानि हुई , उसके स्वरूप और मात्रा की जानकारी विवरण में दी गई है ।

(ग) से (ङ). राज्य में लूनी बेसिन में बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के वास्ते राज्य सरकार ने अन्वेषण और सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिए हैं । राज्य सरकार द्वारा बाढ सुरक्षा की स्थाई स्कीम इसके बाद तैयार की जाएगी ।

विवरण

राजस्थान में बाढ़ों से हुई हानि का स्वरप और मात्रा

1.	प्रभावित क्षेत्र	5.7 लाख हेक्टेयर
2.	प्रभावित जनसंख्या	11.2 लाख
3.	फसली क्षेत्र को क्षति	1.8 लाख हेक्टेयर
4.	क्षतिग्रस्त फसल का मूल्य	2362.9 लाख रुपये
5.	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	93,620
6.	क्षतिग्रस्त मकानों की कीमत	4700 लाख रुपए
7.	मृत पशु	1,13,842
8.	मृत व्यक्ति	478
9.	सरकारी सम्पत्ति और सुविधाओं को क्षति	2994.1 लाख रुपए

बुमसार-कोइलवार तटबंध का निर्माण

874. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुमसार कोइलवार तटबन्ध का शीघ्र निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) :: (क) और (ख). 35.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली बक्सर-कोइलवार स्कीम का क्रियान्वयन

बिहार सरकार द्वारा 1973–74 से चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है और इसके 1979–80 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा थी । इस स्कीम में गंगा, सोन, गंगी (पश्चिम) और गंगी (पूर्व) नदियों के तटों पर कुल 165 किलोमीटर लम्बे तटबंधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है । धन की कमी के कारण, जो 1975 की बाढ़ों के बाद पटना बाढ़, सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की आवश्यकता के कारण और भी बढ़ गई थी, राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम पर अब तक कुल लगभग 7.75 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है । इस स्कीम के लिए 1980–81 के लिए 3 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

Plan for Bagmati Project

875. SHRIMATI RAMDULARI SINHA: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) whether the plan of Bagmati Project is pending finalisation with Government of India for the last several years;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) whether any time limit has been fixed for finalisation of the plan?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) and (b). Bagmati Flood Control Project and Bagmati Irrigation Project were originally approved by the Planning Commission in 1969 and 1970 respectively. Consequent upon shifting of the course of Bagmati river, the Irrigation Project was modified. Subsequently estimated costs of both the projects were also revised. After examination of the revised projects, in consultation with the State Government and after taking into account technical considerations, the State Government were advised in August, 1979 that the irrigation and flood control projects should be integrated into a multipurpose project to deal with irrigation, flood control and drainage as its components. The integrated Bagmati Project received by Central Water Commission from the State Government on 25th February, 1980 is under examination.

(c) No, Sir. After examination of the project it is proposed to have discussions with the State Government Engineers to settle outstanding issues, if any, in order to expedite the clearance of the project

Electricity for Development of Rural Areas in Bihar

876 SHRI R. P. YADAV: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) whether electricity is one of the two main infrastructures for the development of rural areas;

(b) whether Bihar is lacking in this respect; and

(c) if so, what steps are being taken by Government to see that all these villages get electricity?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) Yes, Sir.

(b) Yes. Bihar has achieved only 28.5 per cent rural electrification as against 41.4 per cent in the country as on 31st October, 1979.

(c) The Bihar State Electricity Board has formulated proposals to achieve 100 per cent rural electrification by 1994-95 with funds to the tune of Rs. 497.00 crores. The implementation would, however, depend on the finances available to them. During Sixth Five Year Plan an outlay of Rs. 67 crores has been envisaged for disbursement through R.E.C. in respect of rural electrification schemes in Bihar.